

‘एक देश-एक चुनाव’ का ब्लू प्रिंट

शैलेश कुमार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बड़ी सफलता मिलती दिखाई दे रही है। राजनीतिक सूत्रों का कहना है कि एन.डी.ए. के सहयोगी दल जे.डी.यू., तेलुगू देशम पार्टी और एल.जे.पी. (राम बिलास) 'एक देश-एक चुनाव' और 'धर्म निरपेक्ष नागरिक संहिता' पर सहमत हो गए हैं। जिति जनगणना पर भी सहमति बनती दिखाई दे रही है। मतलब साफ है कि भाजपा 2029 के लोकसभा चुनावों के साथ सभी राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के लिए नया कानून ला सकती है। 'एक देश-एक चुनाव' निश्चित तौर पर एक अच्छी धारणा है। संभव हो तो पंचायतों और नगर परिषदों के चुनाव भी एक साथ ही हो जाएं तो लोकतंत्र के लिए और अच्छी बात होगी। इससे चुनाव के भारी-भरकम खर्च में कमी आएगी। समय की बचत होगी। बार-बार चुनाव के काम में लगा दिए जाने वाले कर्मचारियों को अपना काम कराने का अधिक मौका मिलेगा। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को भी चुनाव पर अधिक खर्च नहीं करना पड़ेगा। इसके चलते राजनीतिक भ्रष्टाचार पर भी थोड़ा बहुत अंकुश लग सकता है। 'एक देश-एक चुनाव' कोई नई बात नहीं है। आजादी के बाद 1952 से 1967 तक लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ ही होते थे। समस्या 1967 के बाद शुरू हुई। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में तो बहुमत मिल गया लेकिन बंगला, बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे कई राज्यों में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। पिछले 5 वर्षों में चुनाव का बढ़ता खर्च देश की अर्थव्यवस्था पर बोझ बनता जा रहा है। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज की एक रिपोर्ट के मुताबिक आजादी के बाद 1952 में देश के चुनाव पर साढ़े 10 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। तब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए थे। 2019 में लोकसभा और आंध्र प्रदेश, उडीसा, अरुणाचल प्रदेश व सिक्किम विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुए जिस पर करीब 50 हजार करोड़ रुपए खर्च हुए। 2024 में ये खर्च बढ़कर करीब 1 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। जाहिर है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते तो लगभग इसी खर्च में दोनों अनुष्ठान पूरे हो जाते। लोकसभा के चुनाव का खर्च केंद्र सरकार और विधानसभा चुनाव का खर्च राज्य सरकार देती है। दोनों चुनाव एक साथ होने पर खर्च दोनों में बंट जाता है। विधानसभाओं के चुनाव अलग-अलग होने से सरकारी तंत्र, मंत्री और राजनीतिक दल हमेशा चुनाव की तैयारी में व्यस्त नजर आते हैं। प्रधानमंत्री और भाजपा सभी चुनावों को एक साथ कराने पर जोऱ दे रहे हैं। लेकिन कांग्रेस सहित ज्यादातर विपक्षी दल एक साथ चुनाव पर सहमत नहीं हैं। खास कर क्षेत्रीय पार्टियों को डर है कि एक साथ चुनाव होने पर सत्ता उनके हाथ से निकल जाएगी। विपक्ष का ये डर बहुत तार्किक नहीं लगता है। केंद्र सरकार के लिए लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराना मुश्किल नहीं है। संविधान की धारा 356 के जरिए विधानसभाओं को भंग करके एक साथ चुनाव कराए जा सकते हैं। इसका उपयोग कई बार हो चुका है। 1977 में जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई तो कांग्रेसी राज्य सरकारों को इसी धारा का उपयोग करके भंग कर दिया गया और राज्यों में विधानसभा के चुनाव कराए गए। 1980 में कांग्रेस केंद्र में लौटी तो राज्यों में जनता पार्टी की सरकारों को भंग करके चुनाव कराए गए। किसी राज्य विधानसभा या लोकसभा का मध्यावधि चुनाव कराने की नौबत आ जाए तो क्या होगा? क्या फिर सभी विधानसभाओं और लोकसभा के एक साथ चुनाव कराए जाएंगे? इसे तर्कसंगत नहीं कहा जा सकता है। एक देश-एक चुनाव के नाम पर केंद्र सरकार को राज्यों में राजनीतिक हस्तक्षेप का अधिकार फिर से देना राज्यों की स्वायत्ता को खत्म करने जैसा होगा। देश में राजनीतिक दलों की भीड़ बढ़ती जा रही है। राज्यों में नए नेता उभर रहे हैं। लोकतंत्र के लिए यह एक शुभ संकेत है। लेकिन क्षत्रप नेताओं की महत्वाकांक्षा एक बड़ी समस्या भी है, जिसके चलते सरकारें 5 साल का समय पूरा नहीं कर पाती हैं। एक देश -एक चुनाव लागू करने पर इस समस्या से कैसे निपटा जाएगा इसका कोई ब्लू प्रिंट अब तक सामने नहीं आया है। प्रधानमंत्री को यह साफ करना होगा कि पूरे कार्यकाल तक सरकार फिर नहीं चले तब क्या होगा? एक रास्ता यह भी हो सकता है कि उम्मीदवारों को बोट देने की जगह पार्टियों को बोट देने की व्यवस्था शुरू की जाए।

पुराण दिग्दर्शन परिचयाध्याय

प्रक्षिप्त-पाठ (भाग-15)

गताक स आग...
गें...

वेद-मूलकता- पुराणों का निमाण वेदग्रन्थों के गूढ़ हरस्यों को स्फुट करने के लिये हुआ है - यह बात प्रायः सभी पुराणों में डंके की चोट घोषित कर दी गई है। निष्पक्ष एवं तरस्य दृष्टि से किसी भी पुराण का पाठमात्र कर लेने से हर एक सहदय का हृदय ही इस घोषणा की सत्यता का साक्षी बन जाता है। बहुत सी वैदिक आख्यायिकाएँ तो पुराणों में शब्द परिवर्तन मात्र के भेद से ज्ञों की त्यों लिखी गई हैं, उदाहरण के लिये-उर्वशी, शुनःशेष, सुदास, हरिश्चन्द्र, विश्वामित्र, वशिष्ठ, देवापि-शनतु, भृगु, अङ्गिरा, नमुचि, दर्धीचि, दिवोदास, त्रित और वृत्रासुर आदि से सम्बन्ध रखने वाली समस्त कथाओं को उपस्थित किया जा सकता है। निरुक्त ग्रन्थ में जहाँ तहाँ ऐसे मन्त्रों की व्याख्या करते हुए अत्रेतिहासमाचक्षते कह कर स्पष्टतया उनमें ऐतिहासिक आख्यानों का अस्तित्व स्वीकार किया गया है। सायान्याचार्य के

३८४



ज्ञान/मीमांसा

मुप्त की संरकृति से पंजाब-हिमाचल की बढ़ी मुश्किलें

लीलत गर्ग

दिल्ली, पंजाब व हिमाचल सरकारों व सम्मुख वित्तीय संकट के धूधलके छाने लगे हैं। सत्ता पर बैठी आम आदमी पार्टी एवं कांग्रेस की सरकारों के सामने चुनाव के दौरान वोटरों को लुभाने के लिए की गयी फीबीज य रेवड़ी कल्चर की घोषणा आर्थिक संकट क बड़ा कारण बन रही है। मुफ्त की रेवड़ीय बाटने एवं लोक-लुभावन घोषणाओं के कितने भारी नुकसान होते हैं, इस बात को दिल्ली पंजाब व हिमाचल सरकारों के सामने खड़ी हु वित्तीय परेशानियों से समझा जा सकता है। इस सरकारों के लागातार बढ़ते राजस्व घाटा व बड़े होती देनदारियां राज्य की अर्थव्यवस्था प भारी पड़ रही हैं। विकास योजनाओं को त छोड़े, इन राज्यों में कर्मचारियों को बेतन द सेवनिनवृत्त कर्मियों को समय पर पेशन देने मुश्किलें आ रही हैं। इन जटिल होती स्थितियों को लेकर 'रेवड़ी कल्चर' पर न्यायालय स लेकर बुद्धिजीवियों एवं राजनीति क्षेत्रों में व्यापक चर्चा है। पंजाब के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की हालियर रिपोर्ट में राज्य की वित्तीय प्राप्तियों और खंडों के बीच बढ़ते राजकोषीय अंतर को उजागर किया गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मुक्त कं संस्कृति पर तीखे प्रहार करते हुए इसे देश वे लिए नुकसानदायक परंपरा बता चुके हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने भी मुफ्त रेवड़ीयां बांटने के चलन पर गंभीर चिंता जत चुके हैं। नीति आयोग के साथ रिजर्व बैंक भ मुफ्त की रेवड़ीयों पर आपत्ति जता चुका है। लेकिन राजनीतिक दलों पर कोई असर नह है।

कैग की रिपोर्ट बताती है कि कैसे पंजाब राज्य का राजस्व घाटा, सकल राज्य घेरेल उत्पाद के 1.99 फीसदी लक्ष्य के मुकाबले 3.87 फीसदी तक जा पहुंचा है। यह बेहत चिंताजनक स्थिति है कि राज्य का सार्वजनिक ऋण जीएसडीपी का 44.12 फीसदी हो गय है। यदि अब भी सत्ताधीश वित्तीय अनुशासन का पालन नहीं करते एवं मुक्त की सुविधाएँ देने से बाज नहीं आते तो निश्चित ही राज्य क बड़ी मुश्किल की ओर धकेलने जैसी बाह होगी। जिसका उदाहरण सामने है कि बीते माह का बेतन निर्धारित समय पर नहीं दिया ज सका है। इसके बावजूद सत्ता पर काबिज नेत मुफ्त की रेवड़ीयों को बांटने का क्रम जारी रखे हुए हैं तो उसको कीमत न केवल टैक्स देने वालों को चुकानी पड़ रही है बल्कि आग लोगों के जीवन पर भी इसका प्रतिकूल अस पड़ रहा है। वर्हीं दूसरी ओर राज्य का खच जहां 13 प्रतिशत की गति से बढ़ रहा है, वर्हीं

A composite image featuring two political figures. On the left, a man with dark hair and a prominent mustache is dressed in a light blue Nehru jacket with four visible buttons. He is positioned behind a microphone stand, looking slightly to his right. On the right, another man with a beard and a yellow turban is seen from the chest up. He is wearing a green and white plaid jacket over a white shirt and is gesturing with his right hand, which is clenched into a fist, while speaking into a microphone. The background is blurred, suggesting an indoor setting like a parliament or a press conference.

राजस्व प्राप्तियां 10.76 फीसदी की दर से बढ़ रही हैं। जाहिर है, ये अंतर राज्य की आर्थिक बदलाली, आर्थिक असंतुलन एवं आर्थिक अनुशासनहीनता की तस्वीर ही उकेरता है। दिल्ली से लेकर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकारें हों या हिमाचल प्रदेश से लेकर अन्य राज्यों में कांग्रेस की सरकारें तमाम तरह की मुफ्त की रेवड़ियां बांट कर भले ही बोट बैंक को अपने पक्ष में करने का स्वार्थी खेल खेला जा रहा हौ, लेकिन इससे वित्तीय बजट लडखड़ाने ने इन राज्यों के लिये गंभीर चुनौती बन रहा है।

दरअसल, जिस भी नागरिक सुविधा को मुफ्त किया जाता है, उस विभाग का तो भट्टा बैठ जाता है। फिर उसका आर्थिक संतुलन कभी नहीं संभल पाता। कैग की हालिया रिपोर्ट बताती है कि पंजाब में एक निर्धारित यूनिट तक मुफ्त बिजली बाटे जाने से राज्य के अस्सी फीसदी घरेलू उपभोक्ता मुफ्त की बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। ये और ऐसी ही अन्य मुफ्त सुविधाओं की भरमार के कारण सरकारों के सामने अपने कर्मियों को समय पर वेतन देने के लिये वित्तीय संकट है, जबकि वेतन पर आश्रित कर्मियों को राशन-पानी, बच्चों की स्कूल की फीस व लोन की ईएमआई आदि समय पर चुकाने में दिक्कत हो रही है। इन जटिल होते हालातों को देखते हुए अपेक्षा है कि राजनेता सस्ती लोकप्रियता पाने के लिये सभिंडी की राजनीति एवं मुफ्त की संस्कृति से परहेज करें और वित्तीय अनुशासन से राज्य की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का प्रयास करें। जब भी ऐसी लोक-लुभावन घोषणाएं की जाती हैं तो उन दलों को अपने घोषणापत्र में यह बात स्पष्ट करनी चाहिए कि वे जो लोकलुभावनी योजना लाने जा रहे उसके वित्तीय स्रोत क्या होंगे? कैसे व कहां यह धन जुटाया जाएगा? साथ ही जनता को सेवना चाहिए कि मुफ्त के लालच में बिगड़ा गया बोट कालांतर उनके हितों पर भाँट पड़ेगा। जनता को गुमराह करते हुए, उन्हें ठहराकर हुए देश में रेवड़ियां बांटने का बादा और फिर उन पर जैसे-तैसे और अक्सर अधे-अधूरे से अमल का दौर चलता ही रहता लोकलुभावन वादों को पूरा करने की लाज अंततः मतदाताओं को खासकर करदाताओं को ही वहन करनी पड़ती है—अक्सर वह अथवा उपकरों के रूप में। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव के समय मुफ्त रेवड़ियां देने के मुद्दे उतारे हुए कहा था कि कई राज्यों ने अपनी वित्तीय स्थिति की अनदेखी करते हुए मुफ्त की सुविधाएं देने का बादा कर दिया है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी कुछ समझदारी पहले उन दलों को आड़े हाथों लिया था, बोट लेने के लिए मुफ्त की रेवड़ियां देने वाले करते हैं। उनका कहना था कि रेवड़ियां बांटने वाले कभी विकास के कार्यों जैसे रेवड़ियां रेल नेटवर्क आदि का निर्माण नहीं करा सकते। वे अस्पताल, स्कूल और गरीबों के घर नहीं बनवा सकते। रेवड़ियां संस्कृति और अर्थव्यवस्था को कमज़ोर करने के साथ आने वाली पीड़ियों के लिए घातक भी सार्वजनिक होती है। इससे मुफ्तखोरी की संस्कृति जल्दी लेती है। मुफ्त की सुविधाएं पाने वाले तमाम लोग अपनी आय बढ़ाने के जरूर करना चाहते हैं। पंजाब में महिलाओं को नगद राशि की घोषणा हुई, जबकि वहां की महिलाएं समृद्ध हैं। दिल्ली में उन महिलाओं को नगद राशि

डाटासो बसा म मुफ्त यात्रा का सुविधा दा गइ है, जिहें इस तरह की सुविधा की जरूरत नहीं। आधी आबादी को मुफ्त यात्रा की सुविधा देने से दिल्ली में डीटीसी को हर साल 15 करोड़ रुपये तक का नुकसान होगा। इस राशि का उपयोग दिल्ली के इन्फ्रास्ट्रक्चर पर किया जा सकता है। मुफ्तखोरी की राजनीति से देश का आर्थिक बजट लडखड़ाने का खतरा है। और इसके साथ निष्क्रियता एवं अकर्मण्यता को बल मिलेगा। हिंदुस्तान में लोगों को बहुत कम में जीवन निर्वहन करने की आदत है ऐसे में जब मुफ्त राशन, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा मिलेगा तो काम क्यों करेंगे।

‘गरोब को थाला मे पुलाव आ गया है, लगता है शहर में चुनाव आ गया है’ भारत की राजनीति से जुड़ी विसंगतियों एवं विडम्बनाओं पर ये दो पंक्तियां सटीक टिप्पणी हैं। चुनाव आते ही वोटरों को लुभाने के लिए जिस तरह राजनीतिक दल और उनके नेता वायदों की बरसात करते हैं, यह शासन-व्यवस्थाओं को गहन अंधेरों में धकेल देता है। मुफ्त की संस्कृति को कल्याणकारी योजना का नाम देकर राजनीतिक लाभ की रोटियां सेंकी जाती रही है। भारत जैसे विकासशील देश के लिये यह मुक्त संस्कृति एक अभिशाप बनती जा रही है। सच भी है कि मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग आज भी इस स्थिति में है कि कथित तौर पर मुफ्त या सस्ती चीजें उसके बोट के फैसले को प्रभावित करती हैं। मुफ्त ‘रेवड़ी’ व कल्याणकारी योजनाओं में संतुलन कायम करना आवश्यक है, परंतु बोट खिसकने के डर से राजनीतिक दल इस बारे में मौन धारण किये रहते हैं, बल्कि न चाहते हुए भी इसे प्रोत्साहन भी देते हैं। फ्रीबीज़’ या मुफ्त उपहार न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में बोट बटोरने एवं राजनीतिक धरातल मजबूत करने का हथियार है। मुफ्त उपहार के मामले में कोई भी देश पीछे नहीं है। ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, फांस, डेनमार्क, स्वीडन, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, मलेशिया, कनाडा, अंगोला, कीनिया, कांगो, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया सहित अनेक देश इस दौड़ में शामिल हैं। विकसित देश जहां अपनी जीड़ीपी का 0.5 प्रतिशत से 1 प्रतिशत तक लोककल्याण योजनाओं में खर्च करते हैं, तो विकासशील देश जीड़ीपी का 3 प्रतिशत से 4 प्रतिशत तक फ्रीबीज़ के नाम पर खर्च कर देते हैं। भारत में अब जब न्यायालय की चौखट पर यह मुद्दा विचाराधीन है, तो संभवना है कि सरकार पर अनावश्यक आर्थिक भार डालने वाली घोषणाओं पर नियंत्रण को लेकर कोई राह भारत ही दुनिया को दिखाए।

विश्व साक्षरता दिवस



महत्वपूर्ण लक्षण से जुड़ा हुआ है। इस तथा को स्पष्ट किया जा सकता है क्योंकि अमेरिका और कनाडा जैसे सभी विकसित देशों में निरक्षरता दर बहुत कम है, जबकि भारत, तुर्की और ईरान जैसे देशों में निरक्षरता की बहुत उच्च दर है। विश्व बैंक के अध्ययन ने एक ओर साक्षरता और उत्पादकता के बीच प्रत्यक्ष और कार्यात्मक संबंध स्थापित किए हैं तो दूसरे ओर साक्षरता पर मानव जीवन की समस्याएँ गुणवत्ता को रेखांकित किया है।

आयु वर्ग के एक व्यक्ति, जो किसी भी भाषा में किसी भी समझ से पढ़ और लिख सकता है, को साक्षर माना जाता है। साक्षरता अधियान राश्ट्रपिता महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय रोजगार गांस्टी योजना के तहत चलाया था। गांधी का सपना था कि भारत में कोई निरक्षर न रहे। भारत में संसार की सबसे अधिक अनपढ़ जनसंख्या निवास करती है। 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत की साक्षरता दर 75.06% है। भारत में उच्चतम और सबसे कम साक्षरता दर के बीच का अंतर बहुत अधिक है। केरल में साक्षरता दर सबसे ज्यादा 94% है, जबकि बिहार में सबसे कम 64% है। भारत में निरक्षरता शहरी और ग्रामीण आबादी के बीच व्यापक अंतराल की विशेषता है। ग्रामीण आबादी मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर करती है और निरक्षरता की दर अधिक है, जबकि शहरी आबादी

आज का इतिहास

1855 स्पेन के क्वीन इसाबेला द्वितीय का द्वार इलोइलो को विश्व व्यापार के लिए खोल दिया गया।

1860 मिशिगन झील पर पैडल स्टीमर लेडी एल्यान का नुकसान लगभग 300 लोग ढूबे।

1900 द 1900 गैल्वेस्टन तूफान से 6,000-12,000 लोगों को मृत्यु हो हुई।

1900 संयुक्त राज्य अमेरिका के टेक्सास शहर के गैलवेस्टोन में चक्रवाती और ज्वारीय तूफान से 6000 लोगों की मौत हुई।

1935 अमेरिकी सीनेट ह्युई लांग को बैटन रूज, लुइसियाना में बुरी तरह से गोली मार दी गई।

1939 गद्दनिया की लड़ाई का आरम्भ हुआ।

1946 बुल्गारिया ने राजशाही का अंत किया।

1950 कांग्रेस द्वारा अनुमोदित रक्षा उत्पादन अधिनियम में मजदूरी और मूल्य नियंत्रण सहित विभिन्न आर्थिक उपायों की आवश्यकता है।

1951 जापान ने 48 देशों के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए।

1954 आठ देशों ने दक्षिण-पूर्व एशियाटी संगठन, नाटो के दक्षिण-पूर्व एशियाई संस्करण बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।

1966 क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ने साउथ वेल्स के लिए एक नए आर्थिक युग के सूत्रपात के रूप में, सेवन ब्रिज को खोला।

1966 संयुक्त राष्ट्र के शिक्षा और सांस्कृतिक विभाग यूनेस्को ने पहली बार विश्व साक्षरता दिवस मनाया।

1974 वाटरगेट कांड-यू.एस. राष्ट्रपति गेराल्ड फोर्ड ने हाल ही में राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को पद पर रहते हुए किए गए किसी भी अपराध के लिए पूर्ण और बिना शर्त, लेकिन कॉन्ट्रोवर्शियल, क्षमा प्रदान की।

1978 ईरानी क्रांति-विरोध की प्रतिक्रिया में इरंडक्लेर के शाह की सरकार के बाद, ईरानी सेना ने ब्लैक फाइटे पर तेहरान में कम से कम 88 प्रदर्शनकारियों को गोली मार दी।

1986 निसान इंग्लैंड में सुंदरलैंड में एक को खोलकर यूरोप में कारखाना खोलने वाली पहली जापानी ॲटोमोबाइल कंपनी के रूप में खुद को स्थापित करता है।

खालिस्तानी समर्थक पार्टी ही गिरा देगी टड़ो की सरकार

अभिनय आकाश

खालिस्तानियों के हमदर्द और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन टूटो की कुर्सी खतरे में आ गई है। बात-बात पर भारत से तकरार रखने वाले जस्टिन टूटो को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब जगमीत सिंह की न्यू डेमक्रेटिक पार्टी (एनडीपी) ने सप्लाई एंड कॉन्फिंडेंस डील से खुद को अलग कर लिया। जगमीत सिंह की एनडीपी जस्टिन टूटो की अल्पमत वाली लिबरल सरकार को सत्ता में बनाए रखने में मदद कर रही थी। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि टूटो के सामने तुरंत में पद छोड़ने और फिर से नए सिरे से चुनाव कराने का खतरा है। लेकिन सरकार गिरने का जोखिम लगातार बना हुआ है। सप्लाई और कॉन्फिंडेंस डील गठबंधन सरकारों से अलग होती है, जहां पर कई पार्टियों संयुक्त रूप से कैबिनेट में काम करती हैं और साथ मिलकर सरकार चलाती है।

जस्टिन ट्रॉपो को अब हाउस ऑफ कॉमन चैंबर में अन्य विपक्षी सांसदों का समर्थन हासिल करना होगा। तभी वो बजट पास करा पाएंगे और विश्वास पत जीत सकेंगे। जगमीत सिंह ने एक वीडियो में कहा कि वो 2022 में दोनों नेताओं के बीच हुए एक समझौते को रद्दी की टोकरी में डाल रहे हैं। उन्होंने ट्रॉप पर दक्षिणपंथी कंजर्वेटिव का मुकाबला करने में सुरक्षम नहीं होने का आरोप लगाया है। सर्वक्षणों से ये संकेत मिलता है कि कंजर्वेटिव अक्टूबर 2025 के अंत तक होने वाले चुनाव में आसानी से जीत हासिल करने के लिए तैयार हैं। एनडीपी की डील से हटने की योजना महीनों से चल रही थी। जगमीत सिंह ने कहा कि लिबरल बहुत कमज़ोर हैं। बहुत स्वार्थी हैं



प्रति समर्पित हैं। वो बदलाव नहीं ला सकते और लोगों की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सकते। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने लोगों को निराश किया है। वो कॉरपोरेट लालच पर अंकुश लगाने में पूरी तरह विफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनका संगठन ही एक ऐसी पार्टी है जो अगले चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी की जीत की कोशिश को नाकाम कर सकती है।

साल 2019 में कनाडा में आम चुनाव हुए थे। टट्टो ने चुनाव में जीत तो दर्ज कर ली थी लेकिन वो सरकार नहीं बना सकते थे। उनकी लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा को 157 सीटें मिली थी। विपक्ष की कंजर्वेटिव पार्टी को 121 सीटें हासिल हुई थीं। टट्टो के पास सरकार बनाने के लिए बहुमत नहीं थी। सरकार बनाने के लिए उन्हें 170 सीटों की दरकार थी। जिसकी बजह से टट्टो की पार्टी ने कनाडा के साइन किया था। ये समझौता की बात कही गई थी। पिछले कनाडा के चुनावों में चीन के मांग की ओर टट्टो पर जबरदस्ती की गई थी। लेकिन उस वक्त जगमीत सिंह लिए ढाल बनकर खड़ी रही। सुरक्षित सिंह भारत के खिलापन के समर्थन में आगे बढ़ते जा रही। जगमीत सिंह ने सरकारी कंजर्वेटिव कटौती के खिलाफ लड़ाई के लिए सरकार से सहयोग की अपनी पार्टी के फैसले का बचाव किया। कर्मचारियों से, सेवानिवृत्ति से, मरीजों से, परिवारों से बचाव किया।

चुनाव में 24 सीटें हासिल करने वाली न्यू डोमोक्रेटिक पार्टी (एनडीपी) का समर्थन लिया। इस पार्टी के मुकिया जगमीत सिंह हैं जो खालिस्तान आंदोलन के बड़े समर्थक हैं। टूटो के लिए सत्ता में रहने का मतलब जगमीत को खुश रखना।

सीईओ को अधिक देने के लिए कटौती करेंगे। उन्होंने कहा कि उदारवादी कॉर्पोरेट हितों के लिए खड़े नहीं होंगे और वह रूढ़िवादी कटौती को रोकने के लिए अगला चुनाव लड़ेंगे। लिबरल और एनडीपी के बीच समझौते ने अल्पमत लिबरल सरकार के अस्तित्व को सुनिश्चित किया। यह संघीय स्तर पर दो पक्षों के बीच पहला ऐसा औपचारिक समझौता था।

समझौते की समाप्ति के साथ, कनाडा पारंपरिक अल्पसंख्यक संसद की राजनीति में लौट आया है। हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं है कि उदारवादी सरकार गिर जाएगी। टूटो के लिए तत्काल कोई खतरा नहीं हो सकता है लेकिन पतन का खतरा है। ब्लूमर्बर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, फिलहाल कनाडाई

चुनाव के बाद सिंह और टूटो ने कॉन्फिडेंस एंड सप्लाई एग्रीमेंट को 2025 तक लागू रहने का साल जब विपक्ष ने हस्तक्षेप की जांच की तरफ अटैक बोला गया। इसकी एनडीपी पाइएम के टूटो के समर्थन से और खालिस्तानी मुद्दे हैं।

कार्यक्रमों में संभावित आगे और भी बड़ी समर्थन वापस लेने के बावजूद किया। उन्होंने कहा कि लोगों से, युवा लोगों के निगमों और अमीर

पाइएम का विश्वास भत पर चुनाव से बचन के लिए मामले-दर-मामले आधार पर संसद में तीन मुख्य विपक्षी दलों में से एक को अदालत में पेश करना होगा। उदारवादी और एनडीपी अभी भी सामाजिक नीति की तरह समान प्राथमिकताएँ साझा करते हैं। दोनों पक्ष संसद में विधेयकों को पारित करने के लिए आने वाले महीनों में इन मुद्दों पर सहयोग और मतदान करना जारी रख सकते हैं।

यह हो सकता है। एनडीपी ने अब पोइलिवर की मांग के अनुसार सौदे से हटकर खुद को आलोचना के लिए खोल दिया है। वह लंबे समय से कहते रहे हैं कि देश को सरकार में बदलाव की जरूरत है और अब एनडीपी का फैसला उनके दावे को और अधिक मजबूती देता है। संक्षेप में कहें तो टूटो के लिए यह बुरी खबर है। उदारवादी कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं, वे जनता का विश्वास खो रहे हैं और ऐसा लगता है कि लगभग नौ वर्षों तक सत्ता में रहने के बाद, कनाडा में परिवर्तन हो सकता है।

भाजपा में हिमंत बिस्ता सरमा का महत्व!, हिंदूत्व के नए पुरोधा?

प्रभु चावला

मुस्लिम विचाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को निरस्त और प्रतिस्थापित करना है।

उनके कानूनों के माध्यम से, सरमा एक तरह से क्षेत्रीय समान नागरिक संस्थानों का ऐतिहासिक अगुआ रही है। लोकन उनकी राष्ट्रीय प्रसिद्धि का श्रेणी भाजपा को जाता है, जिसने उन्हें अपने पाले में ले लिया। इससे पहले, सरमा एक दशक से ज्यादा समय तक धर्मनिरपेक्षता के संबंध विरोधी प्रचार कर रहे। विंडबॉल यह है कि असम में भाजपा से मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी पहली यात्रा युवाहाटी में आरएसएस मुख्यालय की थी। 2015 में जिस दिन से वे पार्टी में शामिल हुए, सरमा की वैचारिक पहचान की भगवा गहराई किसी भी लंबे समय से कार्यरत संघ कार्यकर्ता की मान्यताओं से ज्यादा गहरी हो गई। सरमा अपनी सरकार की उपलब्धियों के बजाय मंदिरों, मुसलमानों, मौलियों और मदरसों के बारे में ज्यादा बात करते हैं।

अपने लचीलेपन, मिलनसरिता और सुलभता के कारण वे 2021 में अपनी पार्टी को दूसरा कार्यकाल दिलाने के लिए सभी को साथ ला रहे। असमिया युवाओं द्वारा 'माम' कहे जाने वाले सरमा का भगवा अवतार उन्हें पूर्वोत्तर के राजनीतिक क्षेत्र का बेताज बादशह बनाता है। सरमा की पुराने हिंदूत्व की अधिकारीयों से संकेत मिलता है कि उन्होंने कांग्रेस की संस्कृति से जो कुछ सोचा था, उसे भूल रखा है।

अपने चुनून विधायी और प्रशासनिक तहत हिंदूत्व के तहत हाल ही में उन्होंने विधानसभा में अल्पसंख्यक यजराम रमेश से गुप्ते में कहा = 'असम के मुख्यमंत्री ने जो कहा वह अस्तीकार्य और निर्दीश है। बीमार दिमाग और बड़बोलापन एक जहरीला मिश्रण है'। सरमा ने पलटवार करते हुए कहा = 'उनको (विपक्ष

को) अल्पसंख्यक वोटों के लिए प्रतिस्पर्धा करने दें। मैं प्रतिस्पर्धा में नहीं हूं।'

वह अपने हिंदू धर्म पर जोर देने और राजनीतिक विरोधियों को किनारे लगाने का कोई मौका नहीं छोड़ता।

पिछले साल भी उन्होंने असम की मुस्लिम आबादी में वृद्धि पर समाल उठाये हुए दावा किया था कि यह प्रति दशक 30 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है, जबकि हिंदूओं के लिए यह दर 16 प्रतिशत है। सरमा ने मुस्लिम संस्थानों को निशान बना रखे हैं, जिनके बारे में उन्हें लगता है कि वे कटूपंथ को बढ़ावा देते हैं।

सरमा एसे आक्रामक युद्धों का स्वागत करते हैं जो

उनके हिंदूत्व की साथ को बढ़ाते हैं। वे विपक्षी दलों द्वारा किसी भी तरह के प्रतिरोध को अपने एंजेंडे को और आगे बढ़ाने के अवसर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। कांग्रेसी होने के नाते, उन्होंने परिवर्तियों को तोड़ने, सरकारों को गिराकर दलबदलतुओं को अपने पक्ष में करने और प्रतिद्वंद्वियों को ध्वस्त करने की कला सीधी थी।

उनकी तेजी से सीखने की कला ने उन्हें सक्षम बनाया है। उन्होंने संघ परिवार के राष्ट्रवादी भाषा के व्याकरण और छंद में महारत हासिल कर ली है। अमित शाह के पसंदीदा सरमा ने अपने गुरु के सामने अपनी योग्यता साखित की है। 2021 में उन्होंने 'अमित शाह एंड द मार्च' को अल्पसंख्यक वोटों के लिए प्रतिस्पर्धा में नहीं हूं।'

वह अपने हिंदू धर्म पर जोर देने और राजनीतिक विरोधियों को किनारे लगाने का कोई मौका नहीं छोड़ता।

उनके आलोचक उनकी शेषी बचावने की आदत से चिढ़ते हैं, जबकि उनके प्रशंसक कटूपंथ के प्रति उनके झुकाका को पसंद करते हैं। यह जटू सरमा की विभिन्न राजनीतिक मिशनों में रणनीतिक चुरुराई में परिलक्षित होता है, जिससे उन्होंने अधिकांश पूर्वोत्तर राज्यों से भाजपा विरोधी, कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकारों को हटा दिया। वे भाजपा को त्रिपुरा जीत के

लिए जिम्मेदार थे।

वे तखावपत्र के मास्टर और चतुर गठबंधन निर्माता हैं। उन्होंने मैटिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नगालैंड में भाजपा का विस्तार किया। ओडिशा में उन्होंने कार्यकर्ताओं को जुटाया और हिंदू काँड़ का भरपूर इस्तेमाल किया। उन्हें आमारी झारखड़ चुनावों के लिए सह-प्रभारी बनाया गया है। उनका पहला कदम पूर्व सीमा चंपाई सोरेन को अपने पाले में लेकर सत्तारूढ़ झामुमों को तोड़ा था।

उन्होंने राज्य में धर्मीकरण का पेंडंग पहले ही तय कर दिया था। उन्होंने 16 मई को रांची में मीडिया से कहा, 'उनको ठंडा मत करो।' हिंदू अभी गम हुआ है, गरम रहने दो। 'जय श्री राम' बोलना शुरू किया है बहुत सालों बाद। ये धर्मनिरपेक्ष लोग हमें ठड़ा करने की कोशिश करेंगे और हमें जय श्री राम नहीं बोलने देंगे। क्या वे नमाज बंद कराया सकते हैं?

स्वाभाविक रूप से सरमा मोदी-शाह के सबसे भरोसेमंद और परखे हुए अनुयायी के रूप में उभरे हैं।

उद्धव वाकरे की सरकार को तोड़ने के दौरान, मौजूदा सीमा एकनाथ शिंदे सहित शिवसेना के सभी बागियों को भगवा सरकार के साता में आने तक असम में सुरक्षित रखा गया था। सरमा की प्रतिभा उनकी कठोर विचारधारा, लचीली शासन कला और व्यावहारिक राजनीति के दुर्लभ संयोजन में निहित है।

उनके प्रवर्तकों द्वारा उन्हें भविष्य के हिंदू 'हृदय स्प्राइट' के रूप में देखा जाता है। क्योंकि सूरज पूर्व में उत्तरा है। सरमा का सितारा मोदी के राज में भी बढ़ रहा है। जूरी अभी भी इस बात पर विचार कर रही है कि वह सुपरस्टार हैं या सिर्फ संघर्ष का धूमकेतु।

उनके हिंदूत्व की साथ को बढ़ाते हैं। वे विपक्षी दलों द्वारा किसी भी तरह के प्रतिरोध को अपने एंजेंडे को और आगे बढ़ाने के अवसर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। कांग्रेसी होने के नाते, उन्होंने परिवर्तियों को तोड़ने, सरकारों को गिराकर दलबदलतुओं को अपने पक्ष में करने और प्रतिद्वंद्वियों को ध्वस्त करने की कला सीधी थी।

उनकी तेजी से सीखने की कला ने उन्हें सक्षम बनाया है। उन्होंने संघ परिवार के राष्ट्रवादी भाषा के व्याकरण और छंद में इस्तेमाल करते हैं। कांग्रेसी होने के नाते, उन्होंने परिवर्तियों को तोड़ने, सरकारों को गिराकर दलबदलतुओं को अपने पक्ष में करने और प्रतिद्वंद्वियों को ध्वस्त करने की कला सीधी थी।

उनकी तेजी से सीखने की कला ने उन्होंने सक्षम बनाया है। उन्होंने संघ परिवार के राष्ट्रवादी भाषा के व्याकरण और छंद में इस्तेमाल करते हैं। कांग्रेसी होने के नाते, उन्होंने परिवर्तियों को तोड़ने, सरकारों को गिराकर दलबदलतुओं को अपने पक्ष में करने और प्रतिद्वंद्वियों को ध्वस्त करने की कला सीधी थी।

उनकी तेजी से सीखने की कला ने उन्होंने सक्षम बनाया है। उन्होंने संघ परिवार के राष्ट्रवादी भाषा के व्याकरण और छंद में इस्तेमाल करते हैं। कांग्रेसी होने के नाते, उन्होंने परिवर्तियों को तोड़ने, सरकारों को गिराकर दलबदलतुओं को अपने पक्ष में करने और प्रतिद्वंद्वियों को ध्वस्त करने की कला सीधी थी।

उनकी तेजी से सीखने की कला ने उन्होंने सक्षम बनाया है। उन्होंने संघ परिवार के राष्ट्रवादी भाषा के व्याकरण और छंद में इस्तेमाल करते हैं। कांग्रेसी होने के नाते, उन्होंने परिवर्तियों को तोड़ने, सरकारों को गिराकर दलबदलतुओं को अपने पक्ष में करने और प्रतिद्वंद्वियों को ध्वस्त करने की कला सीधी थी।

उनकी तेजी से सीखने की कला ने उन्होंने सक्षम बनाया है। उन्होंने संघ परिवार के राष्ट्रवादी भाषा के व्याकरण और छंद में इस्तेमाल करते हैं। कांग्रेसी होने के नाते, उन्होंने परिवर्तियों को तोड़ने, सरकारों को गिराकर दलबदलतुओं को अपने पक्ष में करने और प्रतिद्वंद्वियों को ध्वस्त करने की कला सीधी थी।

उनकी तेजी से सीखने की कला ने उन्होंने सक्षम बनाया है। उन्होंने संघ परिवार के राष्ट्रवादी भाषा के व्याकरण और छंद में इस्तेमाल करते हैं। कांग्रेसी होने के नाते, उन्होंने परिवर्तियों को तोड़ने, सरकारों को गिराकर दलबदलतुओं को अपने पक्ष में करने और प्रतिद्वंद्वियों को ध्वस्त करने की कला सीधी थी।

उनकी तेजी से सीखने की कला ने उन्होंने सक्षम बनाया है। उन्होंने संघ परिवार के राष्ट्रवादी भाषा के व्याकरण और छंद में इस्तेमाल करते हैं। कांग्रेसी होने के नाते, उन्होंने परिवर्तियों को तोड़ने, सरकारों को गिराकर दलबदलतुओं को अपने पक्ष में करने और प्रतिद्वंद्वियों को ध्वस्त करने की कला सीधी थी।

उनकी तेजी से सीखने की कला ने उन्होंने सक्षम बनाया है। उन्होंने संघ परिवार के राष्ट्रवादी भाषा के व्याकरण और छंद में इस्तेमाल करते हैं। कांग्रेसी होने के नाते, उन्होंने परिवर्तियों को तोड़ने, सरकारों को गिराकर दलबदलतुओं को अपने पक्ष में करने और प्रतिद्वंद्वियों को ध्वस्त करने की कला सीधी थी।

उनकी तेजी से सीखने की कला ने उन्होंने सक्षम बनाया है। उन्होंने संघ परिवार के राष्ट्रवादी भाषा के व्याकरण और छंद में इस्तेमाल करते हैं। कांग्रेसी होने के नाते, उन्होंने परिवर्तियों को तोड़ने, सरकारों को गिराकर दलबदलतुओं को अपने पक्ष में करने और प्रतिद्वंद्वियों को ध्वस्त करने की कला सीधी थी।

